(c) what are the names of ports under consideration; and

(d) by when the panel is likely to submit its report?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Yes, Sir. The term of the Adivisory Committee set up to examine the feasibility of setting up a Free Port in the country has been extended upto September, 1991, by which time it is expected that the Committee would submit its report. The reasons for extension of the term of the Committee include, *inter-alia* the need to study one or two existing Free Ports abroad; intesive discussions with the government departments and other agencies concerned and holding of a workshop to ascertain the views of the trade and industry. A number of places in the Southern States and Union Terrorities are under under consideration.

Declaring Sri Sankara University, Kerala as a National University

1278. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to declare Srj Sankara University, Kerala as a National University; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) No, Sir. According to information available in the Department, the Adi Sankeracharya Snskrit University is proposed to be established at Kalady by the Government of Kerala as a State University.

(b) Does not arise.

खर्च में किफायत करने के मामलों में हुई सफलता

1279. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्री ईशदत्त यादव:
श्री गुफरान आज़म:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खर्च में किफायत करने के मामलों में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को फिजूलखर्च को रोकने के संबंधों में जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) सरकारी खर्च में किफायत बरतने के मामले की सरकार निरन्तर पुनरीक्षा करती रहती है। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे विभिन्न मदों पर खर्च में कटौती करें। चूंकि ऐसी मदों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है अतः किफायत करने के बारे में कितनी सफलता मिली है इसकी मात्रा निश्चित कर पाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) अनुदेशों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान नहीं आई है।